>

Title: Need to make all out efforts to provide educational facilities and benefits of reservation to Scheduled Castes to help them join the mainstream of the society.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों के बालकों के गिरते हुए शिक्षा स्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारों द्वारा भरसक प्रयास करने पर भी शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हो रहा है जो चिंता का विषय है।

गरीबी और लाचारी के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में नहीं भेज सकते। आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी बहुत कम लोग होंगे जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भेज सकते हैं। उदारवादी व्यक्ति हर समुदाय में होते हैं, अनुसूचित जातियों के कल्याण की उन्हें भी चिंता है, परंतु आर्थिक पिछड़ापन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। प्रशासन तथा विधायिका की जिम्मेदारी है कि सदियों से उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त किये जाएं। अनुसूचित जातियों के बालकों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना अनेक समस्याओं का समाधान है।

अनुसूचित जाति के बालक शिक्षित होकर अन्य समाज के समान आगे बढ़ेगें तो निश्चित रूप से देश का सर्वांगीण विकास होगा। मैं मानता हूं अनुसूचित जाति के व्यक्ति एकत्र/संगठित होकर अन्य समाज के उदारवादी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करते हुए, संस्थाएं बनाकर इस कठिन कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इस सुंदर स्वप्न को पूरा करने में प्रशासन का उदार होना भी अति आवश्यक है।

मैं इस माननीय सदन के हर सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि वर्ष् 1999 से कुछ उदारवादी व्यक्तियों ने एक संगठन के रूप में उपेक्षित समाज के कल्याणार्थ भावना रखते हुए अपनी शक्ति (मन-तन-धन) से एक शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रयासरत हैं। अनुसूचित जातियों के बालकों तथा सभी समुदाय की कन्याओं को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध् कराने के उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों ने अपने समस्त जीवन की जमापूंजी, कुछ व्यक्तियों ने अपनी कृषिभूमि, कुछ व्यक्तियों ने अपने साधन ट्रैक्टर, टेंकर, निर्माण संबंधी उपकरण आदि तथा जो कुछ नहीं दे सकते थे उन्होंने श्रमदान करने का वचन देते हुए थानागाजी अलवर में एक शिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया। संस्था के कार्य को सफल बनाने के लिए राजस्थान राज्य के लगभग सभी सांसदों/िवधायकों ने प्रशासन से हर स्तर पर गुहार लगाई, परंतु खेद है कि पिछले 4 वर्षों में अनुसूचित जातियों के बालकों तथा सभी समुदाय की कन्याओं को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में संस्था चार इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी।

प्रशासन में बैठे हुए लोगों का विचार है कि - अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ स्थापित संस्थाएं जो अनुसूचित जातियों के बालकों के लिए शिक्षण क्षेत्र में कार्य करना चाहती है, अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ संस्थाएं बनाकर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भूमि को हड़पने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि प्रशासन में अपना एकाधिकार बनाए रखने वाले लोगों को खतरे का आभास है कि अनुसूचित जातियों के बालकों को यदि शिक्षा की सुविधा मिली तो वे अपनी योग्यता के आधार पर उनके बराबर बैठ जायेंगे, फलस्वरूप प्रशासन में उनका वर्चस्व समाप्त हो जायेगा।

अंत में , मैं केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण देने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में आरक्षण दिया जाए। उच्च शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण संस्थान बनायी जाए, जो केवल उपेक्षित समाज के लिए ही हों। गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाली सामाजिक/िशक्षण संस्थाओं को हर प्रकार की प्रशासनिक/वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में उन्हें आरक्षण की ओर देखना ही न पड़ें।